an>

title: Regarding the problem of environmental clearance for brick kilns in the country.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान पूरे देश के अन्दर ईट भट्टों की बन्दी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अन्तर्गत पूरे देश के अन्दर ईट भट्टों में ईट निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह ठप्प पड़ी हुई है। उसके अन्तर्गत कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जो अवैध खनन है, उसे रोका जाए। अवैध खनन में ईट भट्टे नहीं आते हैं, लेकिन पूरे देश के अन्दर फिर भी ईट भट्टों में निर्माण कार्यों के बाधित होने से न केवल विनिर्माण ईकाइयों पर इसका असर पड़ रहा है, अपितु विकास की जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और देश के अन्य क्षेत्रों में चल रही हैं, उन पर भी असर पड़ रहा है। गरीबों के जो मकान बनने हैं, उन पर भी असर पड़ रहा है।

लाखों कामगारों को कार्य भी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 13 हज़ार ईट के भट्टे हैं। महोदय, अभी वह कार्य प्रारंभ न होने के कारण, वहाँ पर विनिर्माण ईकाइयों पर इसका असर पड़ने वाला है। कामगारों को जो कार्य उसके माध्यम से मिलता है, उस पर इसका असर पड़ा है। इसके अलावा अगर ईट का निर्माण नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से ईट के दाम बढ़ेंगे। पहले से ही जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है, उससे कई गुना ज्यादा दाम ईट-भट्टों द्वारा लिया जाता है। गरीबों के नाम पर सरकार के द्वारा जो आवासीय योजनाएँ शुरू की गई हैं, उससे आवास के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। इस समय उन ईट भट्टों को चालू करने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय के यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है परन्तु वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ईट भट्टे नहीं चल पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वन और पर्यावरण मंत्रालय तत्काल देश के सभी ईट भट्टा निर्माण ईकाइयों से जुड़े हुए उन सभी लोगों को बुलाकर उनकी समस्या का समाधान करे। दूसरा, उन ईट भट्टों को प्रारंभ करने के साथ-साथ, क्योंकि उसमें खनन का कहीं भी कोई वॉयलेशन नहीं होता है, वे लोग मिट्टी लेते हैं, मिट्टी से ईट भट्टों का निर्माण होता है और उसके माध्यम से जहाँ वह ईट दें, वहीं उनके दाम भी निर्धारित करने में वह अगर सहयोग करें, इस प्रकार का कोई डायरैक्शन दें जिससे गरीबों के लिए चलने वाली तमाम योजनाओं पर उनका लाभ मिल सके तो मुझे लगता है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से हो पाएगा। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 13 हज़ार ईट भट्टे वर्तमान में बंद चल रहे हैं। वहाँ पर विकास कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है। लगभग डेढ़ लाख कामगार उन भट्टों में कार्य करते हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रति भट्टा एक एक लाख रुपये टैक्स उन लोगों से ले रही है, इसको बंद करवाया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उन सभी निर्माण कार्यों के द्वारा पुनः उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो। इसके लिए जो एन.ओ.सी. यहाँ से दी जानी है, उसको तत्काल दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्रीमती अंजू बाला,

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

श्री दुष्यंत चौटाला,

श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

श्री राहुल शेवाले,

श्री दहन मिश्रा,

श्री जगदम्बिका पाल,

श्री सी.आर.चौधरी,

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह एवं

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।